



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216124
CG-DL-E-13022020-216124

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38।
No. 38।

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2020/माघ 18, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2020/MAGHA 18, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2020

मामला सं. (एसएसआर) 01/2020

चीन जन. गण. एवं कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा।

फा. सं. 7/1/2020-डीजीटीआर—1. जबकि मैसर्स अल्काली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाठन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप घेरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पत्र दायर किया है और चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने तथा उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 14 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/10/2002-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पूर्व में एक जांच शुरू की। प्राधिकारी द्वारा 21 सितंबर, 2002 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/10/2002-डीजीएडी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिनांक 26 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 142/2002-सीमा शुल्क द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। जांच के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 04 अगस्त, 2003 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/10/2002-डीजीएडी द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जिसे चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर दिनांक 23 सितंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 142/2003-सीमा शुल्क द्वारा प्रभावी किया गया था।
4. पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति पर, पाटनरोधी शुल्क दिनांक 21 नवंबर, 2008 के अंतिम जांच परिणाम (संख्या 15/11/2007-डीजीएडी) द्वारा बढ़ाये गये थे। प्राधिकारी के जांच परिणाम दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 137/2008-सीमा शुल्क द्वारा तदनुसार शुल्क निर्धारित किए गए थे।
5. आवेदक के अनुरोध पर, नामित प्राधिकरण ने कोरिया आरपी की अधिसूचना संख्या 15/2/2010-डीजीएडी दिनांक 8 जून, 2010 को आयात के खिलाफ एक मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की। पाटनरोधी शुल्क के संशोधन के लिए सिफारिश अधिसूचना संख्या 15/2/2010-डीजीएडी दिनांक 7 जुलाई, 2011 पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 9.95 / 2011-सीमा दिनांक 3 अक्टूबर, 2011 द्वारा शुल्क की मात्रा को संशोधित किया है।
6. दूसरी निर्णयक समीक्षा 19 दिसंबर, 2013 को शुरू की गई थी जिसके अनुसरण में प्राधिकारी ने दिनांक 18 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/23/2013-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। प्राधिकारी के जांच परिणाम दिनांक 18 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 42/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा तदनुसार शुल्क निर्धारित किए गए थे। संबद्ध देशों पर लगाये गये वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 17 अगस्त, 2020 तक लागू हैं।

विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

7. इस याचिका में विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व की जांचों में है, जिसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक नाम NaOH) है जिसे सामान्य रूप से कोरिया आरओके तथा चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक ऑर्गेनिक, सॉपी, सशक्त अल्कालीन और गंधहीन रसायन है।"

कास्टिक सोडा सीमा शुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आईटीसी आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार यह उत्पाद सीमा शुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

कास्टिक सोडा तीन प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रोसेस, डायफ्रॉम प्रोसेस और मैमरेन प्रोसेस द्वारा दो रूपों अर्थात् लाइ और ठोस रूप में उत्पादित किया जाता है। इव स्वरूप को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है और ठोस स्वरूप को उत्पाद के रासायनिक गुणधर्मों में बिना किसी परिवर्तन के तथा आसानी से द्रव में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस स्वरूप का आसानी से भंडारण और परिवहन होता है जबकि द्रव स्वरूप में आसानी से वृलनशीलता होती है। अंतिम प्रयोग के लिए दोनों स्वरूप प्रतिस्थापनीय और परस्पर परिवर्तनीय हैं। घरेलू उद्योग दो रूपों में कास्टिक सोडा का उत्पादन करता है और वे संबद्ध देशों से आयातों के साथ तुलनीय हैं। अतः उन्हें नियम 2(घ) के अभिप्राय से समान वस्तु माना जा रहा है।

8. चूंकि, यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण गतिविधियां नहीं हुई हैं।

समान वस्तु

9. "समान वस्तु" के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"समान वस्तु" का अभिप्राय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनुरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।"

10. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। अतः घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देशों से आयात की जा रही "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

11. यह याचिका मैसर्स अल्काली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) दायर की गई है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, एसईआईएल केमिकल कॉम्प्लेक्स एंड ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "घरेलू उत्पादक" भी कहा गया है) ने क्षति की जानकारी दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक घरेलू उत्पादक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, "घरेलू उत्पादक" का संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में भारी अनुपात है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध सामानों के सभी उत्पादक एसोसिएशन के भाग हैं और लागू पाटनरोधी शुल्क बढ़ाये जाने के लिए वर्तमान आवेदन पत्र दायर करने का निर्णय एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया था।
12. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार "घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से" किया गया है।

पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आधार

13. आवेदक ने दावा किया है कि चाइना पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार चाइना पीआर के सामान्य मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए चीनी ताइपी को उचित सरोगेट देश माना जाना चाहिए। आवेदक ने चीनी ताइपी में कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा किया है, जो बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट, IHS मार्किट द्वारा अपने आवधिक प्रकाशन, ग्लोबल क्लोर अल्कली रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। ग्लोबल क्लोर अल्काली रिपोर्ट में प्रकाशित कीमतों के आधार पर कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया गया है।
14. आवेदक ने वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय(डीजीसीआईएंडएस) के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्रेशीय भाड़ा व्यय के निमित्त कीमत समायोजन किये गये हैं।
15. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है। इस बात का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक हैं जो यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर निर्यात किये जा रहे हैं और इस प्रकार जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए पाटन की संभावना जारी रहना दर्शाते हैं।

क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा कारणात्मक संपर्क

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के कारण कीमत के निमित्त घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातिकों की निर्यातोन्मुखता तथा क्षमता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिये गये आंकड़े प्रथम दृष्ट्या पाटनरोधी शुल्क के बंद होने पर पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की विस्तार दर्शाते हैं।

निर्णयिक समीक्षा जांच की शुरूआत

17. आवेदकों के विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर पाटन और क्षति जारी रहने/ बार-बार होने की संभावना सिद्ध करने पर और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार स्वयं को संतुष्ट करने पर प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, निर्णयिक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

शामिल देश

18. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य हैं।

जांच की अवधि

19. आवेदक ने अप्रैल 2019-सितंबर 2019 (6 महीने) से जांच की अवधि प्रस्तावित की थी। हालांकि, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 (9 महीने) तक की जांच की अवधि (पीओआई) पर विचार करना उचित पाया है। क्षति की अवधि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल

2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि और जांच की अवधि को कवर करेगी।

प्रक्रिया

20. वर्तमान निर्णयिक समीक्षा में चीन जन. गण. और ताइवान से कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करने वाली 4 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/10/2002-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू तथा चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करने वाली 21 नवंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/11/2007-डीजीएडी और दिनांक 18 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/23/2013-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी यथापेक्षित पाटन एवं क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
21. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

22. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, विषय वस्तुओं से संबंधित ज्ञात भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित तरीके एवं स्वरूप में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अलग से संबोधित किया जा रहा है ताकि वे फार्म में प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें, और नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित तरीके से उनके ज्ञात विचार देने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।
23. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। जानकारी निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जा सकती है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराये जाने के लिए उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।

समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त उप नियम की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह में प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपर्युक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:
- गोपनीय चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)
 - अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।
28. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतर की चार (4) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतर की दो (2) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।
29. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
30. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपर्युक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
31. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।
32. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2020

CASE NO. (SSR) 01/2020

Sunset review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from China PR and Korea RP.

F. No. 7/1/2020-DGTR.—1. Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of Domestic Industry, in accordance with the Custom Tariff Act,1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the Rules), for Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of “Caustic Soda”,(hereinafter also referred to subject goods or product under consideration), originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. The Applicant has alleged likelihood of continuance or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and Korea RP and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duties imposed on the import of the subject goods originating in or exported from China PR and Korea RP.

BACKGROUND

3. The Designated Authority earlier initiated an investigation concerning imports of the subject goods from the China PR and Korea RP vide notification no. 14/10/2002-DGAD dated 14th May, 2002. On the basis of the recommendations made by the Authority, vide Preliminary findings notification no. 14/10/2002-DGAD dated 21st September, 2002, provisional anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 142/2002-Customs dated 26th December, 2002. Pursuant to the investigation, the Designated Authority, vide final findings notification No. 14/10/2002-DGAD dated 4th August, 2003, recommended imposition of definitive anti-dumping duty, which was given effect vide Notification No. 142/2003-Customs dated 23rd September, 2003 on imports of subject goods, originating in or exported from China PR and Korea RP.
4. On expiry of the period of five years, anti-dumping duties imposed were enhanced and extended vide final findings No. 15/11/2007-DGAD] dated 21st November, 2008. Definitive duties were accordingly imposed vide Customs Notification No. 137/2008-Customs dated 26th December, 2008.
5. On the request of the Applicant, the Designated Authority initiated a mid-term review investigation against imports from Korea RP vide Notification No. 15/2/2010-DGAD dated 8th June, 2010. On the recommendation for modification of anti-dumping duties vide Notification No. 15/2/2010-DGAD dated 7th July, 2011, the Central Government modified the quantum of duty vide Notification No.95/2011-Customs dated 3rd October, 2011.
6. The second sunset review was initiated on 19th December, 2013, pursuant to which the Authority recommended continuation of anti-dumping duty vide Notification No. 15/23/2013-DGAD dated 18th June, 2015. Definitive duties were accordingly imposed vide Notification No. 42/2015-Customs (ADD) dated 18th August, 2015. The current anti-dumping duties imposed on the subject countries are in force till 17th August, 2020.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

7. The product under consideration in the petition is the same as the previous investigations, which was defined as follows-

“The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature of NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Korea ROK and China PR. Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical.

Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs head 2815.11 and 2815.12. As per ITC 8-digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 28151102 and 2815.1200.

Caustic Soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e. mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Liquid form can be converted into solid and the solid form can be reconverted in liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable. The domestic industry produces caustic soda in two forms and are comparable with the imports from subject countries, therefore, is being treated as like article within meaning of 2(d) of the Rules.”

8. Since the investigation is a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.

LIKE ARTICLE

9. Rule 2(d) with regard to “like article” provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. The Applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and product under consideration exported from subject countries. Subject goods produced by the domestic producers and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The subject goods are technically and commercially substitutable with imported subject goods. The consumers are using the subject goods interchangeably. Therefore, subject goods produced by the domestic producers are being treated as “like article” to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

11. The application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI). DCW Limited, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited, SEIL Chemical Complex and Grasim Industries Limited (hereinafter also referred to as “Domestic Producers”) have provided injury information. As per the available information, the Domestic Producers have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India. Further, the Domestic Producers account for a major proportion in Indian production of the subject goods. Applicant has submitted that all producers of subject goods in India are part of the Association and the decision of filing of the present application for extension of anti-dumping duty in force was taken by its Executive Committee of the Association.
12. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

13. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has requested to determine normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that Chinese Taipei should be considered as the appropriate surrogate country for determining the normal value for China PR. The Applicant has claimed normal value based on the prices in Chinese Taipei, published by the market research agency report, IHS Markit in its periodic publication, Global Chlor Alkali Report. The normal value for Korea RP have also been claimed on the basis of prices published in Global Chlor Alkali Report.
14. The Applicant has claimed export prices on the basis of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction wise import data. Price adjustments have been

made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight expenses.

15. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) Act. It is noted that dumping margin is above de minimis level. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus indicating continuation likelihood of dumping so as to justify initiation of investigation.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

16. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping. Further, the data provided by the Applicant on the capacity and export orientation of producers/exporters in the subject country also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the Anti Dumping Duty.

INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

17. On the basis of the duly substantiated application of the Applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

SUBJECT COUNTRIES

18. The subject countries in the present investigation are China PR and Korea RP.

PERIOD OF INVESTIGATION

19. The Applicant had proposed period of investigation from April 2019-September 2019 (6 months). However, the Authority has found it appropriate to consider the period of investigation (POI) in the present investigation from 1st April 2019 to 31st December 2019 (9 months). The injury period shall cover the periods 1st April 2016 to 31st March 2017, 1st April 2017 to 31st March 2018, 1st April 2018 to 31st March 2019 and the period of investigation.

PROCEDURE

20. The present sunset review will cover all aspects of the final findings of the original investigation published vide notification no. 14/10/2002-DGAD dated 4th August 2003 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Caustic Soda from China PR and Korea RP and all aspects of the final findings published vide notification no. 15/11/2007-DGAD dated 21st November, 2008 and notification no.15/23/2013-DGAD dated 18th June, 2015, recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Caustic Soda from China PR and Korea RP. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and Injury as required.
21. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

SUBMISSION OF INFORMATION

22. The known exporters in the subject countries and their Government through embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being addressed separately to enable them to file relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

TIME LIMIT

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted. Four (4) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is

claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

34. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

NON-COOPERATION

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority